(ग) प्रकाशक संघ और भारतीय पुस्तक विक्रेता संघ भारतीय प्रकाशक संघ और शैक्षिक प्रकाशक संघ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और भारत के प्रधान मंत्री के कार्यलय सहित संबंधित मंत्रालयों को अभ्यावेदन/ज्ञापन भेज रहे हैं। इन ज्ञापनों में उठाए गए मुद्दों में निम्नलिखित शामिल है;

1. कागजों की कीमतों में वृद्धि।

2. प्रकाशन उद्योग का कमजोर वित्तीय आधार।

3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 क्यू-क्यू के अंतर्गत रियायत वापिस देना।

4. आयात नीति।

5. डाक दर।

6. राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् का पुनर्गठन; और

7. पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन।

सरकार ने वित्तीय प्रशासनिक और अन्य कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रकाशन उद्योग द्वारा प्रकाशित विभिन्न मुद्दों पर विधिवत विचार किया है। राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् का पुनर्गठन किया जा रहा है और इसके पुनर्गठन के बाद इस परिषद् में सभी समस्याओं की समीक्षा की जाएगी।

Decision on Industrial Dearness Allowance

1376. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that members of the officers union of the Public Sector Undertakings could not get an appointment with the Prime Minister for more than two months;

(b) whether it is a fact that the decision on industrial dearness allowance for public sector undertakings is being taken without hearing the members of the officers' union; and

(c) if so, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BHAGEY GOBARDHAN): (a) to (c) Officers are employees of public sector enterprises and as such their associations are required to deal with the management of the public sector enterprises only. In September, 1988, Government set up a Tripartite Committee to review the existing Industrial dearness allowance formula in which both Labour and Managements were represented. The Committee after considerable deliberations could not come to any conclusion. The Government, after considering the deliberations held in the various meetings of the Committee, decided that all the employees of the Public Sector Enterprises should continue to follow the Industrial Dearness Allowance formula with the neutralisation rate being raised from Rs. 1.65 per point rise in AICPI (Simla series, 1960—100) to Rs. 1.90 per point rise from 1-1-1989 beyond AICPI-800. This rate as usual applies to officers and non-officers alike. Since the managements were represented on the Committee, the question of giving hearing to officers unions did not arise.

एन० सी० ई० आर० टी० को लक्ष्य प्राप्ति में विफलता

1377. श्री राम नरेश यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मार्च, 1990 के डक्कन हेराल्ड में "एन० सी० ई० आर० टी० हेज फेल्ड टू रीच टारगेट्स सी० ए० जी०" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन द्वारा लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है; और